राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 204

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, बुधवार, 1 जनवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

नव वर्ष मंगलमय

नए वर्ष का हर्ष सर्वत्र सुख, शांति और सद्भाव लाने वाली सोच को बल प्रदान करे और हम सबको एक नए शिखर की ओर ले जाए, इस आशा और विश्वास के साथ सभी को नूतन वर्ष की शुभकामनाएं

प्रधान संपादक

सपने हों साकार...

दैनिक जागरण सरोकारों के साथ

2020 उम्मीदें

शुरुआत यदि संकल्पों से भरी हो और संकल्प पवित्र हों, सरोकारों से प्रेरित हों, तो सफलता नए आयाम गढ़ बहुआयामी बन जाती है। आइये, नववर्ष-2020 की शुरुआत हम ऐसे ही पवित्र संकल्पों के साथ करें। हमारा हर संकल्प ऐसे सपनों और सरोकारों से भरा हो, जो व्यक्ति, देश और समाज के कल्याण का वाहक बने। आइये नए साल में सर्वकल्याण का महासंकल्प लें, दैनिक जागरण के सात सरोकारों के साथ।

हर दिन नई उम्मीद-हर दिन नव संकल्प... सप्ताहभर चलने वाले संपादकीय अभियान 'उम्मीदें-2020' में हम अपने पाठकों को रूबरू कराएंगे जागरण के उन सात आधारभूत सरोकारों से, जिनकी सतत प्रेरणा कल्याण की ओर ले जाती है। और, इनकी पूर्ति में रत आमजन के उन प्रेरक प्रयासों से भी, जो उम्मीदें जगाते हैं।

डॉ. कलाम, जिन्होंने देश को विजन-2020 दिया, उनकी शिक्षा को आत्मसात कर हम आगे बढ़ें, जो कहती है- सपने वही पूरे होते हैं, जो खुली आंखों से देखे जाएं...।

इस क्रम में हम आपको यह भी बताएंगे कि आने वाले साल में इन सात आधारभूत विषयों की पूर्ति बतौर व्यक्ति, देश और समाज हमारे लिए क्या मायने रखेगी। **मुद्दा** में मंथन भी। (पेज-6)

जागरण विशेष

मजदूर मां-बाप के बेटे ने कहानी सुनाकर जीता दिल

इंदौर : उसने कहानी सुनाई- गिद्ध के कौशल की। आवाज-उच्चारण सुनकर

और भाव-भंगिमाएं देखकर श्रोता दंग थे। मानो कोई मंझा हुआ कलाकार सामने हो। किरदार बदलता तो वह अपनी आवाज बदल लेता...। (पेज-11)

रेलवे ने चार पैसे प्रति किमी तक बढ़ाया किराया, आज से प्रभावी

नई दिल्ली : रेलवे ने यात्री किराए में चार पैसे प्रति किलोमीटर तक की बढ़ोत्तरी की है। नया किराया एक जनवरी, 2020 से प्रभावी होगा, लेकिन पहले से बुक कराए गए टिकट पर इसका असर नहीं पड़ेगा। उपनगरीय ट्रेन के किराए को भी इस बढ़ोत्तरी से बाहर रखा गया है। साधारण दर्जे की नॉन-एसी ट्रेन के किराए में एक पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है। मेल और एक्सप्रेस नॉन-एसी ट्रेन के लिए यह वृद्धि दो पैसे और एसी ट्रेन के किराए में चार पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोत्तरी की गई है। (पेज-3)

इन्फ्रा सेक्टर को नए साल में 102 लाख करोड़ रुपये का तोहफा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का ढांचा तैयार, वित्त मंत्री सीतारमण ने जारी की रिपोर्ट
- आम बजट से ढांचागत क्षेत्र को मिलने वाली राशि में होगी खासी वृद्धि

नई दिल्ली में पांच वर्षों में परियोजना लागू करने का खाका पेश करतीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेट्र

बात पते की

- 42 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स पर काम जारी
- 32 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स का खाका तैयार
- 20 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट बन चुकी
- 19 फीसद सड़क व 16 फीसद शहरी विकास से जुड़ीं
- 24 फीसद परियोजनाएं ऊर्जा क्षेत्र से

विकास को गति देगा यह कदम : इकरा

मुंबई, प्रेट्र : उद्योग जगत ने सरकार के इस फैसले की खुलकर तारीफ की है। अग्रणी रेटिंग एजेंसी इकरा का कहना है कि सकल अर्थव्यवस्था में सुस्ती के इस माहौल में सरकार का यह कदम विकास को गति देने में बेहद मददगार साबित होगा। इस निवेश में कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बड़ी हिस्सेदारी मिलने वाली है। सीबीआरई के चेयरमैन व सीईओ (भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व व अफ्रीका) अंशुमन मैगजीन ने कहा कि यह कदम भारत को दुनिया की अग्रणी इकोनॉमी बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन व एमडी शिशिर बैजल का भी कहना था कि इन्फ्रा ग्रोथ के लिए सरकार की प्रतिबद्धता इस कदम में झलकती है।

प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में 100 लाख करोड़ रुपये की ढांचागत परियोजनाएं शुरू करने की बात कही थी। इस पर सुझाव देने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया था। टास्क फोर्स ने केंद्रीय मंत्रालयों, सरकारी उपक्रमों,राज्य सरकारों समेत निजी क्षेत्र व वित्तीय संस्थानों से विमर्श करने के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है। इसमें केंद्र व राज्य सरकारों की तरफ से चलाई जाने वाली 39-39 फीसद परियोजनाओं समेत निजी सेक्टर से शेष 22 फीसद परियोजनाओं को शामिल किया गया है। रिपोर्ट ने वर्ष 2025 तक निजी सेक्टर की परियोजनाओं का हिस्सा बढ़ाकर 30 फीसद करने की बात कही है। इनमें से 42 लाख करोड़ की परियोजनाओं पर काम जारी है जबकि 32 लाख करोड़ की परियोजनाओं का खाका तैयार है। 20 लाख करोड़ की परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार है। इन्हें जल्द आगे बढ़ाया जाएगा।

वित्त सचिव अतनु चक्रवर्ती ने बताया कि नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत ढांचागत परियोजनाओं के रास्ते की अड़चनों को दूर करने का भी सुझाव दिया गया है। इनके लिए वित्त की व्यवस्था किस तरह से हो, इस पर सरकार आने वाले दिनों में घोषणा करेगी। पिछले छह वर्षों में ढांचागत क्षेत्र पर सरकार की तरफ से 51 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं जबकि अगले पांच वर्षों में कम से कम 102 लाख करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। इस राशि की व्यवस्था के लिए आम बजट में ढांचागत क्षेत्र की मौजूदा हिस्सेदारी 0.83 फीसद से बढ़ाकर 1.3 फीसद करनी होगी। इस राशि से बिजली, रेलवे, रिन्यूअल, शहरी विकास, सिंचाई, स्वास्थ्य, जल क्षेत्र की परियोजनाओं को शामिल किया गया है। यह आम जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के साथ ही देश में रोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि करेगा।

इन क्षेत्रों को इतना मिलेगा : जिन परियोजनाओं को रकम मिलेगी, उनमें से सबसे ज्यादा 24 फीसद परियोजनाएं एनर्जी सेक्टर की है। 19 फीसद परियोजनाएं सड़क व 16 फीसद शहरी विकास से जुड़ी हुई हैं। जबकि रेलवे से जुड़ी 13 फीसद परियोजनाएं हैं। चयनित परियोजनाओं की अब एक निश्चित अंतराल पर समीक्षा होगी।

चालू खाता घाटे पर सरकार को बड़ी राहत पेज>>12

विरोध का तोड़ ▶ सीएए के तहत पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने की तैयारी में केंद्र सरकार

राज्यों की मोहताज नहीं होगी नागरिकता

राज्यों की दखलंदाजी रोकने के लिए जिलाधिकारी को आवेदन नहीं देने पर विचार

- केरल विधानसभा में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास
- तमिलनाडु और महाराष्ट्र भी केरल की ही तरह लाना चाहते हैं प्रस्ताव

केरल विधानसभा भवन। एएनआइ

केरल विधानसभा समेत किसी भी राज्य की विस को नागरिकता पर कोई भी कानून या प्रस्ताव पारित करने का अधिकार नहीं है। **-रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय कानून मंत्री**

नई दिल्ली, एजेंसियां : देश के नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर केरल और केंद्र आमने-सामने आ गए हैं। केरल विधानसभा ने सीएए को हटाने की मांग संबंधी प्रस्ताव पारित किया है। साथ ही वामदल शासित केरल इस कानून को विधानसभा में खारिज करने वाला पहला राज्य बन गया है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। कुछ राज्यों में जारी विरोध को दरकिनार करने के लिए सीएए के तहत नागरिकता देने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की तैयारी है।

इस प्रस्ताव के विरोध में मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा, केरल विधानसभा समेत किसी भी विधानसभा को नागरिकता पर कोई भी कानून या प्रस्ताव पारित करने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में सारी शक्ति सिर्फ संसद के पास है। केंद्र सरकार के कुछ अफसरों के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय नागरिकता ग्रहण करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के जरिये आवेदन देने की मौजूदा प्रक्रिया दरकिनार करने के विकल्प पर विचार कर रहा है। गृह मंत्रालय के अफसरों का कहना है कि अगर सीएए के तहत भारतीय नागरिकता देने की पूरी प्रक्रिया ही ऑनलाइन कर दी जाए तो किसी भी राज्य का किसी भी स्तर पर इस प्रक्रिया में कोई दखल नहीं रह जाएगा। गृह मंत्रालय के वरिष्ठतम अधिकारियों के मुताबिक ऐसा तब करना पड़ रहा है जबकि संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत सीएए को लागू करना सिर्फ केंद्रीय सूची में आता है। केंद्रीय सूची में आने वाले एक केंद्रीय कानून को लागू करने से मना करने का अधिकार किसी भी राज्य के पास नहीं है। सातवीं अनुसूची में आनेवाले 97 विषयों में रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, नागरिकता आदि आते हैं।

तमिलनाडु, महाराष्ट्र में भी मांग : खबर है कि केरल के बाद तमिलनाडु में विपक्षी दल द्रमुक और महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस नेता यहां की विधानसभाओं में नए नागरिकता कानून को खारिज करने की मांग करना चाहते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष मुहम्मद आरिफ नसीम खान ने कहा, केरल की तरह ही महाराष्ट्र विधानसभा में भी सीएए को खत्म करने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। राज्य में कांग्रेस शिवसेना सरकार में साझीदार है। इसीतरह तमिलनाडु में विपक्षी दल द्रमुक ने सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक से केरल की तर्ज पर काम करने का आग्रह किया है। द्रमुक प्रमुख स्टालिन ने फेसबुक पोस्ट में मुख्यमंत्री पलानीस्वामी से कहा कि वह छह जनवरी को तमिलनाडु विधानसभा में भी ऐसा ही प्रस्ताव लाएं। बंगाल सरकार ने भी इस कानून को नहीं लागू करने का एलान किया है।

एकजुट हुए एलडीएफ-यूडीएफ : इससे पहले, 140 सदस्यीय केरल विधानसभा में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ एक प्रस्ताव सत्तारूढ़ माकपा-एलडीएफ और विरोधी दल कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के समर्थन से पारित हुआ है। भाजपा के इकलौते विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री ओ.राजगोपाल ने इसका विरोध किया। सीएए पर चर्चा के लिए एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि केरल में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। साथ ही केरल में राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण रजिस्टर (एनपीआर) की प्रक्रिया को भी आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि सामान्य जनगणना संबंधी गतिविधियों में राज्य सरकार का पूरा सहयोग रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केरल में पंथनिरपेक्षता का एक लंबा इतिहास रहा है। शुरुआत में ईसाई और मुसलमान केरल पहुंचे। हमारी परंपरा समावेशी है। भाजपा विधायक ओ. राजगोपाल ने कहा, विधानसभा में जो कुछ भी हो रहा है, वह असंवैधानिक है। इस बीच, भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्ह राव ने राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू से आग्रह किया कि केरल विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने पर वे केरल के मुख्यमंत्री के खिलाफ संसद के विशेषाधिकार हनन की प्रक्रिया शुरू करें।

बांग्लादेश ने भारतीय सीमा से लगे क्षेत्रों में बंद किया मोबाइल नेटवर्क पेज>>5

सीडीएस की अध्यक्षता में सैन्य मामलों का नया विभाग बना

- रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा यह विभाग, तीनों सेनाओं में बनाएगा समन्वय
- सेनाओं के लिए खरीद, अधिग्रहण, नियुक्ति व अन्य प्रक्रियाओं की संभालेगा जिम्मेदारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ (सीडीएस) की नियुक्ति के बाद सरकार ने इस दिशा में आगे की प्रक्रिया पर कदम बढ़ा दिया है। मंगलवार को रक्षा मंत्रालय में सैन्य मामले विभाग के गठन की घोषणा हुई। नवनियुक्त सीडीएस जनरल बिपिन रावत इसके प्रमुख होंगे। सीडीएस के तौर पर जनरल रावत की नियुक्ति पर सोमवार को मुहर लगी थी। जनरल रावत ने मंगलवार को बतौर सेनाध्यक्ष अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा किया है। बुधवार को नए साल पर वह सीडीएस का पद संभालेंगे।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को सैन्य मामले विभाग के गठन को मंजूरी दी। इस बदलाव के बाद रक्षा मंत्रालय के अधीन कुल पांच विभाग हो गए हैं। इनमें रक्षा विभाग, सैन्य मामले विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा शोध एवं विकास विभाग और पूर्व-सैनिक कल्याण विभाग शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय के अधीन नया सैन्य मामले विभाग सेना की तीनों इकाइयों की खरीद, अधिग्रहण व अन्य प्रक्रियाओं से जुड़े काम देखेगा। साथ ही संयुक्त एवं थिएटर कमान गठन समेत विभिन्न कदमों के जरिये संसाधनों का तर्कसंगत इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए सैन्य कमानों के पुनर्गठन की जिम्मेदारी भी इस विभाग की होगी। यह विभाग तीनों सेनाओं की जरूरतों का एकीकरण करते हुए संयुक्त खरीद, प्रशिक्षण एवं नियुक्ति की प्रक्रिया भी सुनिश्चित करेगा। सेनाओं में स्वदेशी को बढ़ावा देना भी विभाग की जिम्मेदारी होगी।

उल्लेखनीय है कि कारगिल युद्ध के बाद से देश में सीडीएस जैसे पद की मांग उठ रही थी। पिछले स्वतंत्रता दिवस पर संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पद के सृजन की बात कही थी। 24 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी मिल गई थी। 30 दिसंबर को जनरल बिपिन रावत को पहला सीडीएस नियुक्त करने का एलान हुआ था। सीडीएस का कार्यकाल तीन साल और सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होगी।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ (सीडीएस) का शोल्डर रैंक बैज (बाएं), कार का फ्लैग (मध्य में ऊपर), वर्किंग ड्रेस की बटन (मध्य में नीचे), कैप (दाएं, ऊपर) और बेल्ट की बकल ऐसी होगी। प्रेट्र

भारत को आंतकी स्रोत पर हमला करने का अधिकार : जनरल नरवाने पेज>>3

2020 का नयनाभिराम स्वागत

नई उम्मीदों और सपनों के साथ नूतन वर्ष 2020 का आगमन हो गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ओपेरा हाउस और सिडनी हार्बर ब्रिज के पास मनमोहक आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत हुआ। भारत समेत दुनियाभर में नववर्ष का असीम उल्लास नजर आया। रायटर

महाराष्ट्र में ठाकरे मंत्रिमंडल को लेकर असंतोष, कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़

- मंत्री न बनाए जाने से नाराजगी पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत, गठबंधन सरकार में विकल्प सीमित
- प्रणिति शिंदे के समर्थन में यूथ कांग्रेस नेता ने सोनिया गांधी को रक्त से लिखा खत, पार्षद ने दिया इस्तीफा

मुंबई, एजेंसियां : महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही कांग्रेस-राकांपा-शिवसेना गठबंधन में असंतोष सामने आने लगा है। अनुभवी नेताओं की जगह मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल करने पर तीनों दलों के शीर्ष नेतृत्व की उनकी ही पार्टी में आलोचना हो रही है।

पुणे के भोर क्षेत्र से कांग्रेस विधायक संग्राम थोप्टे को मंत्री नहीं बनाए जाने से उनके समर्थक इतने नाराज हो गए कि उन्होंने पुणे स्थित पार्टी के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। हालांकि, सोनिया गांधी के करीबी माने जाने वाले थोप्टे ने मंत्री नहीं बनाए जाने पर कोई टिप्पणी नहीं की है। सोलापुर से कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणिति शिंदे के समर्थक भी उन्हें मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हैं। जिला यूथ कांग्रेस के नेता ने खून से सोनिया गांधी को पत्र लिख कर नाराजगी जताई है। वहीं नगर निगम के एक पार्षद ने इस्तीफा दे दिया है। असलम शेख व विश्वजीत कदम को मंत्री बनाए जाने से भी पार्टी का एक धड़ा खफा है। उनका यह भी कहना है कि शेख और कदम चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होने वाले थे, लेकिन किसी वजह से बात नहीं बनी तो कांग्रेस से साथ बने रहे। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीम खान ने कहा, पार्टी में ऐसी भावना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में वफादारों की अनदेखी की गई है। उम्मीद है कि हाईकमान इस पर गौर करेगा।

मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर बीड के माजलगांव से राकांपा के चार बार से विधायक प्रकाश सोलंके ने सोमवार रात ही कहा था कि वह राजनीति के लायक नहीं हैं और मंगलवार को इस्तीफा दे देंगे। पार्टी के शीर्ष नेता उन्हें मनाने में सफल रहे और उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला बदल दिया।

मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से शिवसेना में भी नाराजगी पेज>>4

स्वच्छता सर्वेक्षण

सर्वेक्षण-2020 के दो तिमाही के नतीजों की सूची जारी, छोटे शहरों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश-हरियाणा के शहरी निकायों का प्रदर्शन शानदार

इंदौर से स्वच्छता का पाठ सीखें भारतीय शहर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नई दिल्ली में मंगलवार को शहरी क्षेत्रों के स्वच्छता सर्वेक्षण-2020 के दो तिमाही के नतीजों की सूची जारी करने के मौके पर प्रेसवार्ता करते केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी (बाएं से दूसरे)। प्रेट्र

देश के शहर मध्य प्रदेश के इंदौर से सबक सीख सकते हैं, जिसे लगातार चौथे साल सबसे स्वच्छ शहर माना गया है। शहरी स्वच्छता में इंदौर, पुणे व भोपाल के शहरी निकायों ने फिर बाजी मारी है। सभी वर्गों की संयुक्त सूची में इन शहरों का स्वच्छता प्रदर्शन शानदार रहा है। छोटे शहरों की सूची में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के शहरों ने शानदार प्रदर्शन किया है। छावनी बोर्ड की स्वच्छता वाली टॉप टेन सूची में उप्र के तीन बोर्डों को जगह मिली है।

शहरी क्षेत्रों के स्वच्छता सर्वेक्षण-2020 के दो तिमाही के नतीजों की सूची साल के आखिरी दिन मंगलवार को यहां जारी की गई। इसमें अप्रैल से जून और जुलाई से सितंबर के बीच स्वच्छता के आंकड़ों के आधार पर यह नतीजा निकाला गया है। संयुक्त वर्ग की टॉप टेन सूची में इंदौर, पुणे के दो शहरी निकाय (जुन्नार व लोनावाला), भोपाल, सूरत, संगोले, नासिक, लैलंगा, बारामती और राजकोट के नाम हैं। 50 हजार से एक लाख की आबादी वाले छोटे शहरों की श्रेणी के टॉप टेन की सूची में उत्तर प्रदेश के छह शहरों बिस्वां, गजरौला, पिलखुआ, गंगा घाट, लहरपुर और गोला गोकर्णनाथ ने स्थान प्राप्त किया है। जबकि 25 हजार से कम आबादी की श्रेणी वाले शहरों की टॉप टेन सूची में झज्जर का बेरी, करनाल का इंद्री, रोहतक का सांपला और यमुना नगर का रादौर शामिल है। इसी वर्ग में उत्तर प्रदेश के सीतापुर का सिंधौली, शाहजहांपुर के खूटर, सीतापुर के पैंटेपुर और कौशांबी के करारी ने अच्छा प्रदर्शन किया है।

देश के 25 हजार से 50 हजार की आबादी वाले शहरों की सूची में पंजाब का नवांशहर, कुराली, पतरान और नांगल ने स्थान बनाया है। जबकि हरियाणा के झज्जर, खरखौंद व गन्नौर को जगह मिली है। इसमें उत्तर प्रदेश के बंसी, मेंहदावल, और मोहम्मदी का नाम भी शामिल है। छावनी बोर्ड की श्रेणी वाले शहरी निकाय में उत्तर प्रदेश का झांसी कैंट, लखनऊ और मथुरा का नाम दस की सूची में है। तीसरे स्थान पर दिल्ली कैंट भी है। जबकि नौवें स्थान पर डलहौजी कैंट का नाम है। सर्वेक्षण में दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की टॉप टेन सूची में पहले स्थान पर इंदौर, दूसरे पर भोपाल और तीसरे पर सूरत का नाम है। जबकि इसके बाद नासिक, राजकोट, पुणे, अहमदाबाद, ठाणे, इलाहाबाद और पालघर का नाम है। इस सूची में कोलकाता सबसे नीचे है। मझोले आकार के एक से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की सूची में पहला स्थान पूर्वी सिंहभूम, सेंट्रल दिल्ली, विलासपुर, कोरबा, खरगांव, रोहतक, ठाणे, सोलापुर और धार के नाम प्रमुख हैं।

सूची जारी करते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि स्वच्छता को लेकर देशव्यापी अभियान में शहरों ने अग्रणी भूमिका निभाई है। पुरी ने स्वच्छता सर्वेक्षण में दिल्ली की 'खराब' रैंकिंग के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 'पूरी तरह से जिम्मेदार' ठहराया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के शहरी क्षेत्र स्वच्छता के मामले में दिल्ली से बेहतर काम कर रहे हैं।'

पीएफआइ पर पाबंदी लगाने के लिए उप्र सरकार ने केंद्र को भेजा पत्र

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- छह माह पूर्व केंद्र को लिखा गया था पत्र, अब गृह विभाग ने भेजा रिमाइंडर
- सीएए के खिलाफ हुई हिंसा में सामने आई थी पीएफआइ की भूमिका

स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) की तरह ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) को भी प्रतिबंधित करने की कसरत शुरू हो चुकी है। कुछ प्रकरण सामने आने पर छह माह पहले राज्य के गृह विभाग ने केंद्र सरकार को प्रतिबंध संबंधी पत्र लिखा गया था। अब नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ हुई हिंसा की आंच इस संगठन पर आने के बाद मंगलवार को गृह विभाग ने केंद्र को रिमाइंडर भेजा है।

सीएए के खिलाफ लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में हिंसा हुई। पीएफआइ के प्रदेश अध्यक्ष वसीम अहमद समेत तीन सदस्यों की लखनऊ में गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस संगठन का अन्य जिलों में नेटवर्क खंगालना शुरू किया। पुलिस को पीएफआइ सदस्यों की खास कर पश्चिमी उप्र में सक्रियता के साक्ष्य मिले। पहले भी आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्टर चस्पा करने के मामलों में दर्ज मुकदमों का रिकॉर्ड खंगाला गया। पिछले दिनों 'जागरण' से बातचीत में डीजीपी ओपी सिंह ने बताया था कि छह माह पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर पीएफआइ पर पाबंदी की सिफारिश की जा चुकी है। इस हिंसा में संगठन का नाम सामने आया। इसमें सिमी के भी सदस्य सक्रिय हैं, इसलिए रिमाइंडर भेजने का फैसला किया गया।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि डीजीपी की ओर से पीएफआइ पर प्रतिबंध संबंधी सिफारिशी पत्र आया था। वह (रिमाइंडर) के रूप में केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है।